AMOGHVARTA
ISSN : 2583-3189

भारत की नई व्यापार नीतियों का आर्थिक प्रभाव

ORIGINAL ARTICLE

Authors
डॉ. राम शंकर पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
स्वामी शुकदेवानन्द कॉलेज
शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
डॉ. रघुबीर सिंह
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
ठाकुर रोशन सिंह संघटक राजकीय
महाविद्यालय, नवादा
दरोबस्त, कटरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध सार

भारत की नई व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, निर्यात बढाना, व्यापार को सरल बनाना तथा घरेलू उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक अवसर प्रदान करना है। यह नीति उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स सुधार, डिजिटल व्यापार प्रणाली मुक्त व्यापार समझौतों के विस्तार और एमईएमएस सेक्टरों की सहभागिता को बढ़ाने पर जोर देती है। नई व्यापार नीति का आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण दर्शाता है कि इससे निर्यात में वृद्धि, रोजगार सृजन, विदेशी निवेश में वृद्धि, तथा निर्माण क्षेत्र का विस्तार होने की संभावना प्रबल है। नीति में व्यापार प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी है, लागतों में कमी आई है और निर्यातकों के लिए समय की बचत हुई है। इसके अतिरिक्त एफटीए के माध्यम से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि इस नीति के लिए कुछ चुनौतियां और समस्याएं भी हैं फिर भी समग्र रूप से नयी व्यापार नीति भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ, निर्यातमुखी, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति दीर्घकाल में भारत को वैश्विक व्यापार शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णय कदम सिद्ध हो सकती है।

मुख्य शब्द

वैश्विक, अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार समझौता, मेक इन इंडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रेडिट गारंटी स्कीम.

प्रस्तावना

भारत ने वैश्विक आर्थिक बाजार में अपनी भूमिका को बढ़ाने और निर्यात आधारित बाजार को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी व्यापार संबंधी नीतियों में बदलाव किया है। विदेश व्यापार नीति 2015–2020 को विस्तारित करने के उद्देश्य से भारत की नई विदेश नीति का शुभारंभ माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया नई। विदेश व्यापार नीति 2023 एक गतिशील अर्थव्यवस्था को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को उनके लक्षण की ओर ले जाती है इस नीति के द्वारा भारत को अपने निर्यात को बढ़ाकर घरेलू निर्माण निवेश, आकर्षण वैश्विक मूल्य, श्रृंखलाओ में अपनी उपस्थिति और आर्थिक सुगमता को मजबूती प्रदान करना है। नई विदेशी व्यापार नीति को लागू करने का उद्देश्य भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाकर बजट एवं व्यापारिक

योजनाओं के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन व्यापार अब संरचना और डिजिटल व्यापार प्रक्रिया को अधिक मजबूती प्रदान करना है। भारत की यह नीति भारत को ग्रीन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक वाहनऔर अन्य आर्थिक विकास वाले सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलवाने की ओर अग्रसर होगी। अच्छी अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात दोनों में ही वृद्धि होनी चाहिए। मुद्रास्फीति और ब्याज की दरे विनिमय दर पर अपने प्रभाव के द्वारा आयात और निर्यात को प्रभावित करती है। इस शोध पत्र में हम नई व्यापार नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उनके आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की समीक्षा करेंगे।

अध्ययन पद्धति

भारत की नई व्यापार नीति का आर्थिक प्रभाव विषय पर किए जाने वाले शोध में प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों का प्रयोग किया जाएगाः

प्राथमिक स्रोतः भारत सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं उनका सक्षम अधिकारी एवं कारोबारी, उद्यमियों, बुनकरों के बीच साक्षात्कार करके आंकड़े ज्ञात करना।

द्वितीयक स्रोतः वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योगों के पंजीकरण की संख्या ज्ञात करना तथा पिछले वर्षों से तुलना करना। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, समाचार पत्रों, टी.वी चौनलों, एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापार नीतियों की जानकारी प्राप्त करके आंकड़े एकत्र करना।

नई व्यापार नीतियों का अध्ययन

भारत के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में निम्न प्रमुख नीतियां अपनाई गई हैंः

अ. नई विदेशी व्यापार नीतिः भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 को भारत के आयात और निर्यात क्षेत्र में निम्न प्रमुख विकास खण्डों में बांटा हैः

- इसमें व्यापार को सरल बनाकर लेनदेन लागत में कमी और ई–पहल को शामिल किया गया है।
- निर्यातकों को धारक के रूप में दर्जा देकर रुपए में में भुगतान स्वीकार करना और जिन शहरों से निर्यात अधिक है उनका विकास करना।
- निर्यात संवर्धन को विकेंद्रीकृत करके जिलों तथा राज्यों को भागीदार बनाना, निर्यात कार्य योजना तैयार करके निर्यात केन्द्रों का विकास करना।
- आई टी प्रणाली को सक्षम बनाकर छोटे ई–कॉमर्स क्षेत्र में कारीगरों, बुनकरों, और अंतरराष्ट्रीय बाजार हेतु निर्यातकों के लिए सहायता प्रदान करना।
- इसमें पूंजीगत वस्तुओं डेयरी क्षेत्र, बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, एवं वस्त्र निर्माण में प्रोत्साहन दिया जाता है।
- व्यापार में विश्वास बढ़ाने हेतु ,मुकदमा घटाने, हेतु प्राधिकरण द्वारा एक मुफ्त माफी योजनाएं भी शामिल हैं।
- इसको नेट प्रणाली के अंतर्गत विशेष रसायन जीव सामग्री उपकरण और प्रौद्योगिकी संबंधी लाइसेंस को सुव्यवस्थित करके वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

ब. मुक्त व्यापार समझौते

भारत में अनेक देशों और क्षेत्रीय समूह के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिनका उद्देश्य है कि वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा और बेचा जा सके, इसके लिए न्यून सरकारी शुल्क, कोटा आदि का प्रावधान है। इनमें प्रमुख समझौते नाफ्टा, विश्व व्यापार संगठन, एएफटीजेड, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, भारत– यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते शामिल हैं।

स. निर्यात प्रोत्साहन

सरकार के द्वारा 6 वर्षीय निर्यात संवर्धन मिशन मंजूर किया गया है जिसकी अवधि 2025–26 से 2030–31 तक होगी। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 25060 करोड़ की लागत को मंजूरी दी है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ई–कॉमर्स निर्यातकों के लिए आसान ऋण योजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य भारत के निर्यात ढांचे को समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

द. भारत ट्रेड नेट

व्यापार को बढ़ाने हेतु भारत ट्रेड नेट को एक एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें दो मुख्य क्षेत्र व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधान शामिल हैं जिसका लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए वैश्विक तकनीकि का लाभ उठाकर अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।

नई व्यापार नीति का आर्थिक प्रभाव

निर्यात वृद्धि और निर्यात विविधीकरण के द्वारा निर्यातकों को बेहतर वित्तीय सहायता, बाजार पहुंचे और लागत में कमी के कारण 2025 में निर्यात लगभग 6 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श और व्यावसायिक सेवा क्षेत्र में उच्च मूल्य वर्धन में सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिया है जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाते हैं। निर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया के मजबूत होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरियॉ और मोबाइल फोन पुर्जे कम लागत में बनने लगे हैं। यह नीति केवल निर्यात को ही नहीं बढ़ाएगी बल्कि घरेलू रोजगार सृजन में भी मदद करेगी ।

डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट से व्यापारिक प्रक्रिया आसान होगी तथा क्रेडिट गारंटी स्कीम का विस्तार एमएसएमई निर्यातकों को बैंकों से सस्ता और जोखिम रहित कर्ज लेने में मदद करेगा जिससे निर्यातकों को अधिक मदद मिलेगी इससे वे अधिक सक्रिय व्यापार में हिस्सा लेंगे।

अधिक निर्यात और विदेशी निवेश से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी डिजिटल प्लेटफॉर्म सुधारो से ट्रेड ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे अनियमिताओं और कर चोरी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। बेहतर घरेलू निर्माण और निर्यात प्रोत्साहन नीतियां भारत की आर्थिक समृद्धि को दीर्घकालिक रूप से स्थिर बना सकती हैं।

भारत के मुक्त व्यापार समझौते और व्यापार विस्तार की नीति उसकी भू–राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान करती है यह नीति भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है साथ ही व्यवसायिक सहयोग बढ़ाने से अन्य देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में सुधार हो सकता है।

चुनौतियां और जोखिम

भारत की नई व्यापार नीति अनेक अवसर लेकर आई है लेकिन उनके क्रियान्वयन में कुछ जोखिम और चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी बाजार पर निर्भर निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि अन्य विकसित देश भी संरक्षण वादी उपाय अपनाएंगे तो भारत की निर्यात नीति की प्रभावशीलता कम होगी।

योजनाओं की घोषणा करना और उनके क्रियान्वयन में अंतर होता है इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वित्तीय प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म वास्तविक रूप से चले। पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन ना होने से छोटे और नवेदित निर्यातक पीछे जाएंगे इसलिए उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक कराई जाए। सीमा बुनियादी ढांचा बंदरगाह सड़क और रेल नेटवर्क की कमी निर्यात लागत में बाधा पहुंचा सकती है।

यदि पर्यावरणीय प्रबंधन और उत्सर्जन नियंत्रण नीति पर्याप्त रूप से नहीं होगी तो दीर्घकालिक परिस्थितियां जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। यदि नीतिगत लाभ बड़े उद्योगों और बड़े निर्यातकों तक ही सीमित होंगे तो आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी। ग्रामीण पिछड़े या संसाधनहीन क्षेत्र में आने वाले छोटे उद्योगों के लिए निवेश और प्रशिक्षण नहीं होगा तो उनको प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होगी इसके सुधार में सरकार को कदम उठाने होंगे।

निष्कर्ष

भारत की नई व्यापार नीति 2023 निर्यात प्रोत्साहन संरचनाए, मुक्त व्यापार समझौते, शुल्क पुर्नसमीकरण और डिजिटल अवसंरचना सुधार दर्शाती हैं कि भारत निर्यात– मूलक और विनिर्माण– उन्मुख आर्थिक प्रयास के पद पर अग्रसर है। यह नीतियां न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती हैं बल्कि देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक

प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाती हैं। हालांकि इन नीतियों को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए चुनौतियां का सामना करना अनिवार्य है जैसे– संरक्षणवाद पर्यावरणीय जोखिम, इंफ्रास्ट्रक्चर बाधाएं और समावेशन। अगर सरकार और संबंधित पक्ष मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें और उपरोक्त नीतिगत सिफारिशो को लागू करें तो भारत इन व्यापार सुधारो का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। भविष्य में निर्यात वृद्धि के साथ–साथ सतत्ता, समावेशन और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना भारत की व्यापार नीति को न केवल आर्थिक दृष्टि से सफल बनाएगी बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी संतुलित बनाए रखेगा।

सुझाव

- महिला– स्वामित्व वाले और पिछड़े क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं बनाई जाएं।
- निर्यात कलेक्टर को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया जाना चाहिए जिससे आर्थिक लाभ अधिक क्षेत्रीय हो।
- डिजिटल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए निर्यातकों और व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
- व्यापार और निर्यात विस्तार के दौरान पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत की जाए।
- निर्यातकों के लिए व्यापार जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण और सलाहकार सेवा विकसित करना चाहिए।
- नीति के सुधारो के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हित धारकों कों शामिल किया जाए ताकि उनको उनकी जरूरत और चुनौतियों को प्रतिक्रियाशील रूप से समायोजित किया जाए।

संदर्भ सूची

1. सिंह, रमेश (2024–25) *भारतीय अर्थव्यवस्था,* मैरूग्रा हिल प्रा. लि., नोयडा।
2. मिश्रा, संजय (2024) *भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आयाम,* इ.डी., नई दिल्ली।
3. कुमार, अरविंद (2018) *भारत की विदेश व्यापार नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,* साहित्य भवन, आगरा।
4. पूरी, बी. के. एवं मिश्रा, एस.के. (2025) *अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,* प्रकाशक का नाम एवं पता ???।
5. मिश्रा, पी. के. (प्रकाशन वर्ष ???) *वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था,* हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई।
6. Salvatore, Dominik (2019) *International Economics,* Wiley India, Noida.
7. Krugman, Paul; Obstfeld, Maurice (2021) *International Economics- theory and policy,* Pearson Education, Noida.
8. Acharya, Shankar (2011) *The Indian economy: A Macroeconomics Perspective,* Oxford University Press, U.K.
9. Kapila, Uma (2021) *Economic development Policy in India,* Academic Foundation, New Delhi.
10. Swami, Subramanian (2007-08) *India and the global economy,* Uma Kapila Academic Foundation, New Delhi.
11. Niti Ayog (2025) The rise of India in global trade, Trade Watch Quarterly Report, Niti ayog Publication, New Delhi, October-December 2025, Q3.
12. भारत सरकार (31 मार्च 2023) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार विदेशी व्यापार नीति 2023–2024, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
13. नीति आयोग (2024) भारत की व्यापार एवं निर्यात वृद्धि रिपोर्ट, नई दिल्ली।

14. भारतीय रिजर्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट– 2023–24, नई दिल्ली।
15. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25, वित्त मंत्रालय भारत सरकार।
16. (2024) व्यापार एवं उद्योग चैंबर भारत के निर्यात क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर 2024।
17. विश्व व्यापार संगठन (2024) भारत की व्यापार नीति समीक्षा 2024, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा।
18. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2024) विश्व आर्थिक दृष्टिकोण।
19. विश्व बैंक (2024) ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट–2024, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी।

––==00==––